वागड़ संदेश

Tital Code RAJHIN27802

जन मन की आवाज

www.wagadsandesh.com

सम्पर्क

ई-पेपर मे खबरे व विज्ञापन के लिये सम्पर्क करें

ई मेल editorwagadsandesh@gmail.com

8890633631
9309255545
6351581818

वर्ष-1 अंक-298 सागवाड़ा,बुधवार,20 जुलाई, 2022 अवधि: हिन्दी ई-पेपर पृष्ठ-1, मूल्य-10 रु. (वार्षिक)

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी डूंगरपुर जिले में क्वार्ट्ज और गिट्टी का अवैध खनन रोका जा सकेगा ?

*** मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक में को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर अवैध खनन रोकने को कहां**

*** अवैध खनन में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करने के निर्देश**

डूंगरपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवास पर अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गंभीर है। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर बिना किसी भी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो। भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

जिला पुलिस अधीक्षक खनन माफियाओं की पहचान कर सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले यह सुनिश्चित करें। अवैध खनन परिवहन करने वालों से ज्यादा अवैध खनन व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। ऐसी गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करें, ताकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन को अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना राशि को रिवाइज करने के निर्देश दिए। खनन, पुलिस, परिवहन और प्रशासन समन्वय बनाकर कार्रवाई करें। बैठक में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे कि अवैध खनन करने के लिए वाहनों का क्षेत्र में संचालन ही नहीं हो। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें, ताकि वे अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रोक सकें तथा एम-सैंड को भी प्रोत्साहित किया जाए। गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कार्रवाई में ग्रामीणों का सहयोग लेकर बड़ी मशीनरी पर कार्रवाई करें।

राजस्व राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि औचक अभियान चलाए जाएं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में सुधार के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। नए ब्लॉक के ऑक्शन से सरकार को 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है। वर्तमान सरकार ने गत सरकार के साढे तीन साल के कार्यकाल से अधिक कार्रवाई की है। इसमें गत सरकार में 35,803 प्रकरणों की तुलना में 41,239 प्रकरण दर्ज किए। पहले 33,738 वाहन जब्त किए गए थे, जबकि अभी 41,074 वाहन जब्त किए गए। इसके साथ ही साढ़े तीन वर्षों में अवैध खनन पर कार्रवाई कर 418 करोड़ रूपये का जुर्माना भी वसूला गया।

आठवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

एक लाख 25 हजार का लगाया आर्थिक दंड, डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

डूंगरपुर। जिले की पोक्सो कोर्ट ने एक आठवी कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी किया है। पीडिता की माँ ने 11 जनवरी 2021 को धम्बोला थाने में मामला दर्ज करवाया था। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र का है। पीडिता की मां ने धम्बोला थाने में 11 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था की 26 दिसम्बर 2020 को वह अपने पीहर किसी काम से गई हुई थी। वही उसके पति मजदूरी के लिए गुजरात में थे। इधर उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 8 वी की छात्रा घर पर अकेली थी। वही रात को जब नाबालिग की माँ पीहर से लौटी तो घर पर उसकी बेटी नहीं थी। जिस पर पता चला की पारडा दरियाटी निवासी भरत पिता लवजी उसे बोलेरो में बैठाकर उसे ले गया है। नाबालिग की माँ की रिपोर्ट पर धम्बोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शूरू की। वही इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया की भरत उसका अपहरण करके ले गया था और उसे अलग-अलग जगहों पर रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर पुलिस ने आरोपी भरत को गिरफ्तार किया। वही अनुसन्धान पूरा करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी भरत को दोषी करार दिया। वही दोषी भरत को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

जनता के काम नहीं करने वाले अधिकारियों को जयपुर से बाहर का रास्ता दिखाओं: खाचरियावास

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने में आनाकानी करने और फाइलों को बेवजह अटकाने वाले कर्मचारी-अधिकारी अब खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निशाने पर है। खाचरियावास ने कर्मचारियों-अधिकारियों को राजधानी से बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी दी है। आज अपने आवास से स्कूटी वितरण के बाद मीडिया से पूछे गए एक सवाल पर बोलते हुए खाचरियावास ने कहा कि अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी ये गलतफहमी में है कि उसे कोई नहीं हटा सकता है तो वह उसे दूर कर ले। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस के नेता पुष्पेन्द्र भारद्वाज सफाई, रोड लाइट और प्रशासन शहरों के संग अभियान में धीमी गति से पट्टे देने के मुद्दे पर धरना देकर बैठे थे। इस मामले पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए खाचरियावास ने कहा जब सरकार ने पट्टे जारी करने में हर तरह की छूट दे रखी है तो फिर अधिकारियों-कर्मचारियों को किस बात की परेशानी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास ये आखिरी मौका है और अब भी अगर उन्होंने अभियान के दौरान कोई लापरवाही बरती तो अब सीधे बाहर ही भेजा जाएगा।

आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली बीटीपी ने किया समाज के साथ धोखा

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बीटीपी विधायक पर राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालने पर साधा निशाना

डूंगरपुर। राष्ट्रपति पद चुनाव के तहत डूंगरपुर जिले के चौरासी विधायक राजकुमार रोत द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेने पर राजनीति गरमाती जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीटीपी विधायक राजकुमार रोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा की आदिवासियों के नाम पर राजनैतिक रोटिया सेक कर विधायक बने राजकुमार रोत ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व पूर्व मंत्री सुशील कटारा की ओर से डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने कहा की एनडीए ने देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। और 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था। एनडीए के अलावा ऐसी कई पार्टिया थी जिसने आदिवासी महिला होने के नाते राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया और वोट किया। लेकिन प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में आदिवासियों व आदिवासी समाज के नाम पर विधायक बने चौरासी विधायक राजकुमार रोत ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में भाग ही नहीं लिया।

जिस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने कहा की आदिवासियों के नाम पर राजनैतिक रोटिया सेक कर विधायक बने राजकुमार रोत ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। आदिवासी समाज उन्हें इस काम के लिए काफी माफ नहीं करेगा। वही उन्होंने समाज के लोगो से विधायक इस सम्बन्ध में सवाल करने का भी आव्हान किया। इधर पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने कांग्रेस सरकार भी निशाना साधा। उन्होंने कहा की कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश में किसानो को बीज खाद नहीं मिल पा रहा है। वही प्रदेश की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। कांग्रेस राज में कांग्रेस विधायको की मंत्री नहीं सुन रहे तो बेचारी आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा की प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले विधान सभा चुनाव में राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की एक सशक्त सरकार बनने का उन्होंने दावा भी किया है।

कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर प्रभारी पहुंचे डूंगरपुर

कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से की चर्चा, चुनाव को लेकर लिए आवेदन

डूंगरपुर। जिले में कांग्रेस संगठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से नियुक्त प्रभारी यशपाल सिंह आज डूंगरपुर पहुंचे। जिन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से चर्चा की वही जिला अध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्षों के लिए आवेदन लिए है। इधर आवेदनों पर सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति में चुनाव करवाए जायेंगे। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस संगठन चुनाव लम्बे समय से पेंडिंग चल रहे है। लेकिन लम्बे इन्तजार के बाद अब संगठन चुनाव की प्रकिया शुरू हो गई है। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से नियुक्त प्रभारी यशपाल सिंह आज डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर पहुँचने पर प्रभारी यशवंत सिंह ने सर्किट हाउस में पहले कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओ की बैठक ली। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नेताओं व कार्यकर्ताओ से सर्वसम्मति से अपना जिला अध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्ष बनाने को लेकर आव्हान किया। वही बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने अध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्षों के लिए आवेदन लेकर उसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान द्वारा करने का प्रस्ताव भी पारित किया। इधर प्रस्ताव पारित होने के बाद संगठन प्रभारी यशपाल सिंह ने एक अलग कमरे में कांग्रेसी नेताओ व कार्यकर्ता से अलग-अलग बातचीत की और अध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्ष पदों के लिए आवेदन लिए। इस मौके पर संगठन प्रभारी यशपाल सिंह ने कहा की संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए जा रहे है। उन्होंने बताया की आवेदनों के आने के बाद उन पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जायेगी वही सर्वसम्मति नहीं होने पर कांग्रेस आलाकमान द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार चुनाव करवाए जायेंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय का इन्तजार

कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन कर विरोध जताया

डूंगरपुर। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मार्च माह से पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है। कार्मिको को राज्य सरकार से मिलने वाला मानदेय तो मिल रहा है लेकिन केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय नहीं मिल रहा है। जिले की कुल 3572 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के एक करोड़ 60 लाख 14 हजार राशि का इन्तजार है। इधर बकाया मानदेय को लेकर कार्मिको ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी जैन के नेतृत्व में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिकाये कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी जैन ने बताया डूंगरपुर जिले में महिला एवं बाल अधिकारिता की ओर से 1646 आंगनबाड़ी केंद्र व 471 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। जिसमे 3 हजार 572 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिकाये कार्यरत है। जिनको राज्य सरकार के मद से 3900 रुपए व केंद्र सरकार के मद से 4500 रुपए का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया की सभी कार्मिको को राज्य सरकार के मद से मिलने वाले मानदेय का तो भुगतान कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मार्च माह से अभी तक का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री के बयान के विरोध में डूंगरपुर जिले के सरपंच भी लामबंद

पंचायतों में तालेबंदी कर सरपंचों ने जताया आक्रोश

डूंगरपुर। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेशचन्द्र मीणा द्वारा नागोर व बाड़मेर जिलों में करोडो के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बयान के मामले में डूंगरपुर जिले के सरपंच भी लामबंद हो गए है। राजस्थान सरपंच संघ के आव्हान पर डूंगरपुर जिला सरपंच संघ के निर्देश पर डूंगरपुर जिले की सभी 353 पंचायतो में सरपंचो ने तालेबंदी करके आक्रोश जताया। वही मंत्री मीणा को पद से हटाने की मांग की है।

प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेशचन्द्र मीणा द्वारा नागोर व बाड़मेर जिलों में करोडो के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मामला गर्माता जा रहा है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले का सरपंच संघ भी मंत्री के खिलाफ लामबंद हो गया है। पंचायत राज मंत्री रमेशचंद्र मीणा को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आव्हान पर आज जिलेभर के सरपंचों ने खुद अपने हाथो से पंचायतो पर तालाबंदी की। जिला सरपंच संघ अध्यक्ष लीलाराम वरहात ने बताया की पंचायत राज मंत्री रमेश मीना की तानाशाही से पूरे प्रदेश में कामकाज ठप है। विभाग थम गया है, मंत्री ने जब से पदभार संभाला है उसी दिन से प्रदेश में पंचायत राज की कमर टूट गई है। बजट नहीं होने से पंचायतों का कामकाज बंद है , और आमजन विकास ठप होने से त्रस्त है। इधर, प्रदेश की की बाड़मेर व नागोर जिलो में करोडो के भ्रष्टाचार के बयान व जांचे करवाकर सरपंचो को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जिसके चलते सरपंचो में नाराजगी है। उन्होंने बताया की मंत्री के खिलाफ पूरे प्रदेश में सरपंच आज एकजुट है और पंचायतों पर तालाबंदी की गई। सरपंचो ने सीएम से रमेश मीणा को पंचायतीराज मंत्री के पद से हटाने की मांग की है। इधर पंचायतों पर तालाबंदी से ग्रामीण काफी परेशान दिखाई दिए और लोग पंचायत परिसरों के चक्कर लगाते दिखे।

1000 ड्रोन करेंगे किसानों की मदद, ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई का भविष्य, राज्य में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता

आधुनिक तकनीक आधारित खेती से बढ़ेगी किसानों की आय: गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया। हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित कर इन्हें धरातल पर उतारा जाए। गहलोत मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य कृषि बजट की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कृषि प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कृषि संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिल सकें। उन्होंने योजनाओं का प्रदेश में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाकर प्रक्रियात्मक पारदर्शिता में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ड्रिप इरिगेशन से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। राजस्थान जैसे मरूस्थलीय प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। किसानों का इस तरफ रूझान बढ़ा है। सरकार इसके उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभांवित करने के लिए 1705 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के लिए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत 1.60 लाख कृषकों को सिंचाई संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी क्रम में बजट में घोषित 825 करोड़ की सब्सिडी के अंतर्गत अब तक 9,738 फार्मपौण्ड व 1,892 डिग्गियों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वहीं, किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए 22,807 कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सोलर पंपों पर सरकार द्वारा 61.58 करोड़ का अनुदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई में पानी की बचत वाली स्कीमों पर लगभग 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इन योजनाओं के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार व प्रगतिशील किसानों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा।

लॉरेंस गैंग ने दी विधायक बेनीवाल को जान से मारने की धमकी

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल को बुधवार सुबह एक धमकी भरा खत मिला है। लेटर कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है। लेटर में लिखा है- मिस्टर बेनीवाल गाड़ी गायब होने वाले दिन से तुम्हारा उल्टा समय शुरू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लेना। जल्दी ही तुम्हारा काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। JAY SOPU (जय सोपू)। लेटर के सबसे नीचे विधायक के नागौर निवास का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। जय सोपू को पुलिस लॉरेंस विश्नोई गैंग से जोड़कर देख रही है। सोपू ग्रुप लॉरेंस का बनाया हुआ है। यह पंजाब के विश्वविद्यालयों का छात्र संगठन है। MLA बेनीवाल ने बताया कि वो अपने नागौर आवास पर थे। बुधवार सुबह करीब 8 बजे उन्हें अपने घर के चौबारे में एक लिफाफा पड़ा दिखा। उन्होंने उसे चेक किया। लिफाफे के अंदर लेटर था। उसमें उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। नारायण बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी नागौर MP हनुमान बेनीवाल को दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हाल हैं। कभी शांत रहने वाले इस स्टेट में अब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उधर, सूचना मिलते ही नागौर SP राममूर्ति जोशी, ASP राजेश मीणा समेत कोतवाली व सदर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। विधायक से जानकारी ली जा रही है।

खनन माफियाओं पर कार्यवाई हो, पुलिस अपना इकबाल कायम करे: गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गंभीर है। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर बिना किसी भी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो। गहलोत ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक खनन माफियाओं की पहचान कर सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ?से वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन परिवहन करने वालों से ज्यादा अवैध खनन व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। ऐसी गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करें, ताकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सके। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन को अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना राशि को रिवाइज करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि खनन, पुलिस, परिवहन और प्रशासन समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।